

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2019/फाल्गुन 23, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 753
No. 48]	DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2019/PHALGUNA 23, 1940	[N.C.T.D. No. 753

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2019

सं. 295/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद्वारा उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड V, अध्याय 6-L में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

वर्तमान अध्याय 6-L के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा :

भाग L

किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत निर्मित नियम

(1) संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ:

- ये नियम 'दिल्ली उच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति नियम, 2018' कहलायेंगे।
- इनका विस्तार नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण अधिकारिता पर होगा।

(iii) ये नियम इनके दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(2) **परिभाषाएँ:** इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) “अधिवक्ता” से अभिप्राय है ऐसा अधिवक्ता जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित दिल्ली बार काउंसिल द्वारा यथावत पंजीकृत हो।
- (ii) “समिति” से अभिप्राय है इन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत गठित “वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु समिति”।
- (iii) “उच्च न्यायालय” से अभिप्राय है दिल्ली उच्च न्यायालय।
- (iv) “पूर्ण न्यायालय” से अभिप्राय है उच्च न्यायालय के सभी उपस्थित न्यायाधीश।
- (v) “महानिबंधक” से अभिप्राय है उच्च न्यायालय के महानिबंधक।
- (vi) “सचिवालय” से अभिप्राय है इन नियमों के नियम 4 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्थापित सचिवालय।

(3) **समिति:** दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति से सम्बंधित सभी मामलों पर एक समिति – “वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु समिति” द्वारा विचार किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- (i) माननीय मुख्य न्यायाधीश – समिति के अध्यक्ष
- (ii) उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
- (iii) उच्च न्यायालय हेतु भारत के अतिरिक्त महा सॉलिसिटर
- (iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों में से उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए
- (v) उपरोक्त द्वारा नामित बार का सदस्य

(4) **सचिवालय:**

- (i) समिति का एक सचिवालय होगा जिसका गठन माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के परामर्श से होगा।
- (ii) सचिवालय के कार्य के सम्बन्ध में उस रीति एवं स्रोत जिससे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एवं सूचना एकत्रित, संगृहीत एवं प्रस्तुत की जानी है को शामिल करते हुए समिति समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(5) **पात्रता शर्तें:** कोई व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि-

- (i) उसने कम से कम 10 वर्षों तक बार में अधिवक्ता के रूप में वकालत न की हो;
- (ii) वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित बार काउंसिल में नामांकित न हो;
- (iii) वह मुख्यतः दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ न्यायालय में वकालत न कर रहा हो; तथा
- (iv) वह लोक कल्याण के मुकद्दमों में उपस्थित न हुआ हो तथा बहस न की हो अथवा विधिक सेवा प्रदान न की हो।

स्पष्टीकरण: व्यावसायिक अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम अनुभव के सम्बन्ध में योग्यता शर्तें, दिल्ली के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों अथवा जिन्होंने 10 वर्षों की सेवा तथा/या अनुभव के पश्चात् पद त्याग किया हो, तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए लागू नहीं होंगी।

(6) **मतार्थना:** वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु किसी प्रत्याक्षी द्वारा मतार्थना उसे ऐसी नियुक्ति हेतु अयोग्य करेगी।

(7) **किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :** दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु या तो (क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरणा से अथवा (ख) वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संयुक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(क) स्व प्रेरणा की प्रक्रिया:

- (i) किसी अधिवक्ता पर जो पूर्व विहित योग्यता शर्तों को पूरा करता हो, या तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिखित प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु, स्व प्रेरणा से विचार किया जाएगा।
- (ii) किसी न्यायाधीश अथवा माननीय मुख्य न्यायाधीश का ऐसा लिखित प्रस्ताव महानिबंधक को भेजा जायेगा जो सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा विधिवत भरे एवं हस्ताक्षरित सहमति-एवं-वैयक्तिक सूचना पत्र (इन नियमों का अनुलग्नक-क) प्राप्त करने के पश्चात इसे सचिवालय को भेजेंगे।

(ख) वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त प्रस्ताव की प्रक्रिया:

- (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में व्यक्तिगत वकालत पाँच वर्षों से कम न हो किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय को संयुक्त रूप से प्रस्ताव देंगे।
- (iv) बशर्ते कि ऐसा कोई वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्ण न्यायालय द्वारा निरंतर दो विचारणों में दो से अधिक नाम प्रस्तुत नहीं करेगा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार दिए गए प्रस्ताव हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होंगे एवं इनकी एक प्रति प्रस्ताव(वों) को देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सचिवालय में ऐसे प्रस्ताव(वों) के जारी होने के चार सप्ताह के भीतर फाइल की जाएगी।
- (v) तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का ऐसा संयुक्त प्रस्ताव महानिबंधक को भेजा जाएगा जो सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा विधिवत भरे एवं हस्ताक्षरित सहमति-एवं-वैयक्तिक सूचना पत्र (इन नियमों का अनुलग्नक-क) प्राप्त करने के पश्चात इसे सचिवालय को भेजेंगे।

(8) **सचिवालय द्वारा डाटा का संकलन:** किसी अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रस्ताव सहित सभी प्रस्ताव प्राप्त होने पर सचिवालय:

- (i) किसी विशिष्ट अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव को उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन के चार सप्ताह अथवा समिति द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य समयावधि के भीतर उनकी प्रस्तावित नियुक्ति में अन्य पणधारियों के सुझाव/मत आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगा;
- (ii) निम्न के सम्बन्ध में अधिवक्ता(ओं) का डाटा एवम सूचना संग्रह करना जिनमें शामिल हो –
 - (क) ख्याति, आचरण एवं सत्यनिष्ठा;
 - (ख) लोक-कल्याण कार्यों में सह-भागिता;
 - (ग) नियुक्ति के प्रस्ताव से पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाशित निर्णयों की संख्या जिनमें सम्बंधित अधिवक्ता उपस्थित रहा हो; तथा
 - (घ) अधिवक्ता(ओं) के बारे में ऐसी अन्य जानकारी जिसका समिति द्वारा विशिष्ट रूप से निदेश दिया गया हो; तथा

(iii) उप-नियम (i) के अंतर्गत सुझाव/मत प्राप्त होने पर तथा उप नियम (ii) के अंतर्गत डाटा एवं सूचना संग्रहण के पश्चात, सचिवालय सम्बंधित अधिवक्ता(ओं) का डेटाबेस तैयार करेगा तथा उसे समिति के समक्ष रखेगा।

- (9) **समिति द्वारा मूल्यांकन:-** समिति किसी अधिवक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त के प्रत्येक प्रस्ताव की सचिवालय द्वारा संगृहीत किये गए डाटा को ध्यान में रखते हुए जांच करेगी तथा सम्बंधित अधिवक्ता का साक्षात्कार भी लेगी। इसके पश्चात समिति सम्बंधित अधिवक्ता का निम्न अंक आधारित संरूप के आधार पर अपना समग्र मूल्यांकन करेगी :-

क्र.सं.	विषय	अंक
1.	नामांकन की तिथि से आवेदक अधिवक्ता द्वारा वकालत के वर्ष [10-20 वर्षों की वकालत के लिए 10 अंक; 20 वर्षों से अधिक की वकालत के लिए 20 अंक]	20 अंक
2.	सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा मुकद्दमे की कार्यवाही के दौरान दिए गए विधि सूत्र को दर्शाने वाले निर्णय (प्रकाशित एवं अप्रकाशित); सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा किये गए लोक-कल्याण कार्य; विधि के विशेष क्षेत्रों में प्रक्षेत्र विशेषज्ञ	40 अंक
3.	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	15 अंक
4.	साक्षात्कार/बातचीत के आधार पर व्यक्तित्व एवं योग्यता का परीक्षण	25 अंक

(10) **पूर्ण न्यायालय:**

- समिति द्वारा समग्र मूल्यांकन के पश्चात, इसके समक्ष सूचीबद्ध सभी नामों को इनकी मूल्यांकन रिपोर्ट सहित पूर्ण न्यायालय को पेश किया जाएगा। सामान्यतः पूर्ण न्यायालय, अपरिहार्य स्थिति के अतिरिक्त, गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान का सहारा नहीं लेगी।
- गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान की स्थिति में, पूर्ण न्यायालय के निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा लिए जायेंगे जिन्होंने अपनी प्राथमिकता/चयन का प्रयोग किया है, जब वर्तमान न्यायाधीशों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई न्यायाधीशों ने अपना मतदान किया हो, मतदान करने वाले न्यायाधीश की पूर्ण न्यायालय सभा में उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ध्यान दिए बिना।
- पूर्ण न्यायालय को अपने निर्णयों के कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(11) **मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं की वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्ति:**

- पूर्ण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता(ओं) का नाम स्वीकृत होने पर, मुख्य न्यायाधीश उस अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के अंतर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेंगे।
- महा निबंधक इस नियुक्ति के बारे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के महा सचिव, दिल्ली बार काउंसिल, भारतीय बार काउंसिल तथा उच्च न्यायालय के अधीन सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी सूचित करेंगे।
- समिति की कार्यवाहियों का अभिलेख तथा इस बारे में पूर्ण न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख सचिवालय द्वारा सन्दर्भ हेतु रखा जाएगा।

(12) **पुनरीक्षण/पुनर्विचार:**

- यदि वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु किसी प्रस्ताव पर पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुकूलतः विचार नहीं किया जाता है तो सम्बंधित अधिवक्ता(गण) ऐसे विनिश्चय होने की तिथि से दो वर्ष तक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं होंगे एवं इसकी सूचना सम्बंधित अधिवक्ता(गण) तथा प्रस्तावकों को दी जायेगी।
- सम्बंधित अधिवक्ता(गण) के सम्बन्ध में पूर्ण न्यायालय के निर्णय पर इसके पश्चात उपरोक्त विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नए प्रस्ताव के रूप में ही, पुनरीक्षण/पुनर्विचार किया जाएगा।

(13) पदनाम वापस लेना

- (i) किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के आचरण का दोषी होने की दशा में जो कि पूर्ण न्यायालय के अनुसार सम्बद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता को उस पदनाम पर बने रहने के योग्य होने से अनधिकृत करता है तो पूर्ण न्यायालय सम्बद्ध व्यक्ति की नियुक्ति के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा एवं उसे वापिस लेगा।
- (ii) वापसी की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसा कि नियम 10 के उप-नियम (ii) के अंतर्गत दी गई है।
- (iii) महानिबंधक वापसी के निर्णय की सूचना उसी प्रकार देंगे जैसा कि नियम 11 में दिया गया है।

(14) निरसन एवं व्यावृत्ति: उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु अधिसूचना सं. 529/नियम/डीएचसी दिनांक 14.12.2012 द्वारा बनाए गए नियम एतद्वारा निरसित किये जाते हैं। किन्तु यह निरसन अपने आप निरसित नियम/दिशा निदेश के अंतर्गत किए गए कार्य को अमान्य नहीं करेगा।

अनुलग्नक-‘क’

बायोडाटा, सहमति एवं वचन का प्रारूप

क्रम सं.	विवरण	
1.	नाम:	
2.	पिता/पति का नाम:	
3.	पता तथा फ़ोन नंबर, ईमेल पते सहित:	
4.	जन्म तिथि:	
5.	अर्हताएं:	
6.	अधिवक्ता के रूप में नामांकन की संख्या एवं तिथि तथा नामांकन का स्थान:	
7.	तिथि जब से वकालत में निरन्तर कार्यरत हैं तथा वकालत का स्थान:	
8.	यदि राज्य न्यायिक सेवा के पूर्व सदस्य हैं तो सेवा की अवधि और वकालत का अनुभव:	
9.	विधि की विभिन्न शाखाएं जिनमें विशिष्ट अनुभव हो :	
10.	विधि के प्रश्न वाले महत्वपूर्ण मामलों का ब्यौरा, जिनमें पिछले 5 वर्षों से उपस्थित रहे हों तथा इस अवधि के दौरान प्रकाशित मुकद्दमों के उद्धरण	
11.	उन मुकद्दमों का ब्यौरा जिनमें पिछले तीन वर्षों में किसी अन्य अधिवक्ताओं (अपने चैम्बर/ कार्यालय के अतिरिक्त) की ओर से बहस करने वाले अधिवक्ता के रूप में उपस्थित रहे हों तथा उन अधिवक्ताओं का नाम व ब्यौरा जिनके लिए उपस्थित हुए हों।	
12.	उन लेखों का ब्यौरा, यदि कोई किसी पत्रिका में प्रकाशित हुए हों अथवा कोई प्रकाशन अथवा पुस्तक जिसका लेखन किया हो	
13.	क्या किसी विश्वविद्यालय/ कॉलेज में विधि विभाग से जुड़े हैं, यदि हाँ तो ब्यौरा दें	

14.	उन मुकद्दमों का ब्यौरा जिनमें लोक-कल्याण हेतु उपस्थित हुए हों तथा/ अथवा निशुल्क विधि सहायता दी हो (जहां उपलब्ध हो, आदेश संलग्न करें)	
15.	क्या भारतीय बार काउंसिल, दिल्ली बार काउंसिल अथवा किस अन्य राज्य की बार काउंसिल के समक्ष किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में लिप्त रहे।	
16.	क्या किसी अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से लिप्त रहे।	
17.	क्या इनके विरुद्ध कभी किसी आदेश/निर्णय में कोई टिप्पणी की गई।	
18.	कोई अन्य सूचना जो विद्वान अधिवक्ता देना चाहें।	
19.	क्या दिल्ली उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले कभी और प्रस्ताव/सहमति की तिथि से एक वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर आपको वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया गया ? (यदि किसी न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रस्ताव लंबित हो तो उसके बारे में भी बताएं) :	

नोट : उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यदि इस प्रारूप में दिया गया स्थान अपर्याप्त लगे तो अलग पृष्ठ का भी प्रयोग किया जा सकता है।

सहमति

मैं _____ अधिवक्ता, एतद्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16(2) की शर्तों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त होने हेतु अपनी सहमति देता हूँ तथा तत्समय प्रवृत्त या इसके पश्चात इस हेतु विहित किये जाने वाली समस्त विधियों, नियमों, विनियमों, मानदंडों एवं दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन एवं सहमति देता हूँ।

वचन

मैं वचन देता हूँ कि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने पर, मुझे विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किसी प्राधिकरण द्वारा नियत किये गए लोक-कल्याण के मुकद्दमों में उपस्थित होऊंगा।

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर

न्यायालय के आदेशानुसार

हस्ता./-

दिनेश कुमार शर्मा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th March, 2019

No. 295/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966), Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Chapter 6-L, Volume V of High Court Rules & Orders :-

The following shall be substituted for the existing Chapter 6-L:-

Part L**RULES FRAMED BY THE HIGH COURT OF DELHI UNDER SECTION 16(2) OF THE ADVOCATES ACT, 1961 FOR DESIGNATING AN ADVOCATE AS SENIOR ADVOCATE****(1) Short title, extent and commencement: -**

- (i) These rules shall be called ‘The High Court of Delhi Designation of Senior Advocate Rules, 2018’.
- (ii) These Rules shall extend to the entire jurisdiction of the High Court of Delhi at New Delhi.
- (iii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

(2) Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires:

- (i) “Advocate” means an Advocate who is duly registered with the Bar Council of Delhi constituted under the Advocates Act, 1961.
- (ii) “Committee” means the “Committee for Designation of Senior Advocates” as constituted under Rule 3 of these Rules;
- (iii) “High Court” means the High Court of Delhi
- (iv) “Full Court” means all the Judges of the High Court present
- (v) “Registrar General” means the Registrar General of the High Court
- (vi) “Secretariat” means the Secretariat established by the Chief Justice of the High Court under Rule 4 of these Rules.

(3) Committee:- All matters relating to designation of Senior Advocates by the High Court of Delhi shall be dealt with by a Committee – “Committee for Designation of Senior Advocates” comprising of the following members:-

- (i) Hon’ble the Chief Justice – Chairperson of the Committee
- (ii) Two Senior most Judges of the High Court
- (iii) Additional Solicitor General of India for the High Court
- (iv) To be nominated by the Administrative Committee of the High Court out of the names of three Senior Advocates given by the Government of NCT of Delhi
- (v) Member of the Bar nominated by the above

(4) Secretariat:-

- (i) There shall be a Secretariat of the Committee, composition of which will be as directed by Hon’ble the Chief Justice in consultation with the other members of the Committee.
- (ii) The Committee may issue such directions from time to time as deemed necessary regarding functioning of the Secretariat, including the manner in which, and the source/s from which, the necessary data and information with regard to designation of Senior Advocates are to be collected, compiled and presented.

(5) **Eligibility Conditions:** No person shall be eligible for being designated as Senior Advocate unless he/she -

- (i) has practiced as an Advocate at the Bar for not less than 10 years;
- (ii) is enrolled with a Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961;
- (iii) has been mainly practising in the High Court of Delhi and the Courts Subordinate to it; and
- (iv) has appeared and argued cases or provided legal services pro-bono.

Explanation: The eligibility condition with regard to minimum standing as a practising Advocate shall not apply to retired Judicial Officers of Delhi or those who have resigned having service and / or practice of 10 years at their credit and retired High Court Judges.

(6) **Canvassing:** Canvassing by a nominee for designation as a Senior Advocate shall disqualify him for being so designated.

(7) **Procedure for designation of an Advocate as Senior Advocate.** An advocate may be considered by the High Court for being designated as Senior Advocate either (A) Suo Motu by the High Court or (B) on a Joint Proposal by Senior Advocates

(A) Procedure Suo Motu:

- (i) An Advocate who fulfills the eligibility conditions prescribed hereinbefore, may be considered suo moto by the High Court for being designated as a Senior Advocate either on the written proposal of a Judge of the High Court or of Hon'ble the Chief Justice of the High Court.
- (ii) Such written proposal of a Judge or of Hon'ble the Chief Justice shall be sent to the Registrar General who shall forward it to the Secretariat after obtaining a consent – cum – personal information sheet (**Annexure-A to these Rules**) duly filled in and signed by the Advocate concerned.

(B) Procedure on Joint Proposal by Senior Advocates:

- (iii) Three Senior Advocates designated by Delhi High Court, with not less than five years individual standing at the Bar, as Senior Advocate, may jointly make a proposal to the High Court for designation of an Advocate as Senior Advocate.
- (iv) Provided that no such Senior Advocate shall propose more than two names in two consecutive considerations by the Full Court and that the proposal(s) so made by the Senior Advocate shall be signed and dated and a copy of the same shall be filed by the Senior Advocate making the proposal(s) with the Secretariat within four weeks of the date of issuance of such proposal(s).
- (v) Such joint proposal of three Senior Advocates shall be sent to the Registrar General who shall forward it to the Secretariat after obtaining a consent – cum – personal information sheet (**Annexure-A to these Rules**) duly filled in and signed by the Advocate concerned.

(8) **Compilation of Data by the Secretariat:** On receipt of all proposals including written proposals by the Judges for designation of an Advocate as Senior Advocate, the Secretariat shall:-

- (i) Publish on the official website of the High Court the proposal for designation of the particular Advocate as Senior Advocate for inviting suggestions / views of other stakeholders in his / her proposed designation within four weeks of such publication on the website of the High Court or such other period as may be prescribed by the Committee;
- (ii) Collect data and information of the Advocate(s) concerned regarding his / her:-
 - (a) Reputation, conduct and integrity;
 - (b) Participation in pro-bono work;
 - (c) Number of reported judgments in which the Advocate(s) concerned appeared for the last five years preceding the proposal for designation; and
 - (d) Such other information about the Advocate(s) concerned as may be specifically directed by the Committee; and
- (iii) On receipt of suggestions / views under sub-rule (i) and collection of data and information under sub-rule (ii), the Secretariat shall compile a database of the Advocate(s) concerned and put up the same before the Committee

(9) **Assessment by the Committee:-** The Committee shall examine each proposal for designation of an Advocate as Senior Advocate in the light of the data compiled by the Secretariat and shall also interview the concerned Advocate. The Committee shall then make its overall assessment of the concerned Advocate on the basis of the following point based format:-

S. No.	Matter	Points
1.	Number of years of practice of the Applicant Advocate from the date of enrolment. [10 points for 10-20 years of practice; 20 points for practice beyond 20 years]	20 points
2.	Judgments (Reported and unreported) which indicate the legal formulations advanced by the concerned Advocate in the course of the proceedings of the case; pro bono work done by the concerned Advocate; Domain Expertise in Specialized Areas of law	40 points
3.	Publications by the Applicant Advocate	15 points
4.	Test of Personality & Suitability on the basis of interview/interaction	25 Points

(10) **Full Court:**

- (i) After the overall assessment by the Committee, all the names listed before it will be submitted to the Full Court along with its Assessment Report. Ordinarily, the Full Court may not resort to voting by secret ballot, except when unavoidable.
- (ii) In the event of resort to secret ballot, decisions of the Full Court will be carried by a majority of the Judges who have chosen to exercise their preference / choice, where at least two-thirds of the total strength of the sitting Judges have cast their ballot, irrespective of the Judge casting ballot being present or not in the Full Court meeting.
- (iii) The Full Court shall not be required to record reasons for its decision(s).

(11) **Designation of Advocates as Senior Advocates by the Chief Justice:-**

- (i) On the approval of the name of the Advocate(s) by the Full Court, the Chief Justice shall designate such an Advocate as a Senior Advocate under Section 16 (2) of the Advocates' Act, 1961.
- (ii) The Registrar General shall notify the designation to the Secretary General of the Supreme Court of India, the Bar Council of Delhi, Bar Council of India and also to all the District and Sessions Judges subordinate to the High Court.
- (iii) A record of the proceedings of the Committee and the record received from the Full Court in this regard shall be maintained by the Secretariat for reference.

(12) **Review/Reconsideration:**

- (i) If a proposal for designation as Senior Advocate is not favourably considered by the Full Court, the Advocate(s) concerned would be ineligible for being recommended for designation as a Senior Advocate for a period of two years from the date of such decision and intimation thereof being sent to the proposers and the Advocate(s) concerned.
- (ii) The decision of the Full Court in respect of the Advocate(s) concerned may thereafter be reviewed/reconsidered by following the procedure prescribed above, as if the proposal is being considered afresh.

(13) **Recall of Designation:**

- (i) In the event a Senior Advocate is guilty of conduct which according to the Full Court disentitles the Senior Advocate concerned to continue to be worthy of the designation the Full Court may review its decision to designate the concerned person and recall the same.
- (ii) The procedure for recall shall be the same as provided under sub-rule (ii) of Rule 10.
- (iii) The Registrar General shall notify the decision of recall in the same manner as provided for in Rule 11.

(14) Repeal and Saving: The Rules framed by the High Court vide notification No. 529/Rules/DHC dated 14.12.2012 for designating an Advocate as Senior Advocate are hereby repealed. However, this repeal shall not, by itself, invalidate the actions taken under the repealed rules / guidelines.

ANNEXURE – 'A'

PROFORMA OF BIO-DATA, CONSENT AND UNDERTAKING

SL No.	PARTICULARS	
1.	Name:	
2.	Father's/Husband's Name:	
3.	Address with Contact Number and E-Mail address:	
4.	Date of birth:	
5.	Qualification:	
6.	No. and date of enrolment as an Advocate and where enrolled:	
7.	Date from which continuously practising and place where practising :	
8.	If a former member of the State Judicial Service, length of such service and the experience at the Bar:	
9.	Fields of specialty in branches of law:	
10.	Particulars of important matters involving questions of law in which appeared in the last five years, and particulars of citations of reported cases during this period	
11.	Particulars of cases in which appeared as arguing Counsel on behalf of other Advocates (not being from own chamber / office) during the preceding three years and the names and particulars of the Advocates on whose behalf appeared	
12.	Particulars of articles, if any published in any journal or publication or books if any authored	
13.	Whether associated with any Faculty of Law of any University/College, if yes provide particulars	
14.	Particulars of cases in which appeared pro-bono and / or free legal aid given (where available, enclose orders)	
15.	Whether involved in any disciplinary proceedings before Bar Council of India, Bar Council of Delhi or Bar Council of any other state. If so the particulars/result/stage of the proceedings	
16.	Whether personally involved in any contempt proceedings	
17.	Whether any remark has ever been passed against him/her in any order/judgment by any Court of Law	

18.	Any other information which the learned Advocate may like to furnish.	
19.	Whether considered for designation as Senior Advocate by the Delhi High Court or any other High Court or Supreme Court at any time and also within one year prior to the date of proposal/consent (Also state if proposal pending with any Court):	

Note : Separate sheet can be used for providing answers to the aforesaid questions, if the space in this proforma is considered insufficient.

CONSENT

I Advocate, do hereby consent to be designated as a Senior Advocate in terms of Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and agree and undertake to abide by all laws, rules, regulations, norms and guidelines as are in force for the time being, or which may be prescribed hereafter for this purpose.

UNDERTAKING

I undertake that upon designation as Senior Advocate, I shall appear and argue pro-bono cases as assigned to me by any Authority under the Legal Services Authorities Act, 1987.

PLACE:

DATE:

SIGNATURE

By Order of the Court

Sd./-

DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General